



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 503] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25, 1972/अग्राहायण 4, 1894

No. 503] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 1972/AGRAHAYANA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 25th November 1972

S.O. 725(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of opinion that India Machinery Company Limited, Howrah, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (hereinafter referred to as the said Act), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the body of persons (in this order referred to as the Board of Management) comprising of—

Chairman

1. Shri A. Bose, Special Officer and *Ex-Officio* Secretary, Department of Closed and Sick Industries, Government of West Bengal, Calcutta.

Members

2. Shri Birendra Chandra Pal, Care of the Industrial Reconstruction Corporation of India, Limited, Calcutta.
3. Shri N. Ghose, Technical Adviser, Industrial Reconstruction Corporation of India, Limited, Calcutta.

to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, India Machinery Company Limited, Howrah, subject to the following terms and conditions namely:—

- (i) the Board of Management shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) the Board of Management shall hold office for five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette; and

(iii) the Central Government may terminate the appointment of any of the persons comprising the Board of Management earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 25(26)/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1972

का० आ० 725(अ)/18 ए/आई डी आर ए, 72-यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इण्डिया मशीनरी कंपनी लिमिटेड, हावड़ा, औद्योगिक उपक्रम का, जिसकी बाबत उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 के अधीन अन्वेषण किया जा चुका है, प्रबंध लोकहित में अन्यन्त हानिकर रीति से किया जा रहा है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18-क की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों,

अध्यक्ष

1. श्री ए० बोस, विशेष अधिकारी और पदेन सचिव, बंद और अव्यवस्थित उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।

सदस्य

2. श्री विरेन्द्र चन्द्र पाल, मार्फत भारत का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता
3. श्री एन० घोष, तकनीकी सलाहकार, भारत का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता ।

से गठित निकाय को (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् प्रबंध मंडल कहा गया है) उक्त उपक्रम, अर्थात् इण्डिया मशीनरी कंपनी लिमिटेड, हावड़ा, का पूर्ण प्रबंध निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन ग्रहण करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (i) प्रबंध मंडल केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए सभी निदेशों का पालन करेगा ;
 - (ii) प्रबंध मंडल राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पदासीन रहेगा ; और
 - (iii) केन्द्रीय सरकार, प्रबंध मंडल में के किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, पहले ही समाप्त कर सकेगी ।
2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

[सं० फा० 25(26)/72-सी-यू-सी]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।